



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 2008/आश्विन 11, 1930

No. 357]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2008/ASVINA 11, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जॉब शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2008

विषय : चीन जन. गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों के सम्बन्ध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/18/2008-डीजोएडी.-यतः मै. जयश्री टेक्सटाइल्स ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपरचात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपरचात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण. और हांगकांग (जिन्हें एतदपरचात् सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स (जिसे एतदपरचात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आरोपित पाटन के सम्बन्ध में पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।

और यतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि सम्बद्ध देशों द्वारा सम्बद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक सम्बन्ध का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है, अतः प्राधिकारी उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो वसूल किए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी,

1833 GU/2008

एतदपरचात् आरोपित पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच शुरू करते हैं।

घरेलू उद्योग

2. घरेलू उद्योग की ओर से तथा सात अन्य विनिर्माताओं के समर्थन से मै. जयश्री टेक्सटाइल्स (आदित्य बिरला न्यूव लि. की एक इकाई) द्वारा आवेदन दायर किया गया है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदकों के पास घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) तथा नियम 5(3) के अनुसार पाटनरोधी जांच हेतु मामला दायर करने के लिए आधार मौजूद है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्स से बुना हुआ फैब्रिक है जिसमें 30% से अधिक फ्लैक्स घटक युक्त होता है। फ्लैक्स तथा लिनेन समानार्थी हैं और "फ्लैक्स" शब्द "लिनेन" के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग फ्लैक्स फाइबर्स से बने यार्न तथा फैब्रिक के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। प्रायः इसका उपयोग सामान्य रूप से बुधन बेंड, बाध, टेबल तथा किचन टेक्सटाइल्स के एक वर्ग के उत्प्लेख के लिए भी किया जाता है क्योंकि परम्परागत रूप से तैलियों, चमरों आदि के लिए फ्लैक्स का उपयोग बहुलता से किया जाता है। पहले इस शब्द का प्रयोग हल्के अंतर-परिधानों जैसे कमीजों, कुरतियों, वेस्ट शर्ट्स, लिंगरी तथा वियोज्य शर्ट कॉलर तथा कफ के लिए भी किया जाता था।

4. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अध्याय 53 के अंतर्गत उप-शीर्ष 53.09 में वर्गीकृत है। यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके विनिर्मित उत्पादों और सम्बद्ध देशों से आयातित सम्बद्ध वस्तुओं में कोई विशेष अंतर

नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित फ्लैक्स फैब्रिक भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के रूप में चीन तथा हांगकांग से भारत में आयोजित फ्लैक्स फैब्रिक के साथ तुलनीय है। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर सम्बद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

शामिल देश

6. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन गण और हांगकांग है।

सामान्य मूल्य

7. आवेदक का प्रस्ताव है कि चीन के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार किया जाए। आवेदकों ने सूचित किया है कि वह ऐसे तीसरे देश से अन्य के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। तदनुसार, आवेदक का प्रस्ताव है कि चीन के सम्बन्ध में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में कीमतों तथा (ख) भारत में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों एवं लाभ को शामिल कर विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया जाए। याचिकाकर्ता ने हांगकांग के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया।

निर्यात कीमत

8. उपलब्ध कीमतें सीआईएफ निर्यात कीमतें हैं। आवेदक द्वारा निवल निर्यात कीमत का निर्धारण भी सीआईएफ कीमत के आधार पर किया गया है तथा कारखाना निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े कमीशन आदि के समायोजन के विभिन्न घटकों को अपना कर किया है।

पाटन घाटित

9. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य है कि सम्बद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य उनकी निवल निर्यात कीमतों से बहुत अधिक है, जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति तथा कारणोत्पन्न सम्बन्ध

10. आवेदक ने आरोपित पाटन के परिणामस्वरूप पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के कारण उनके बाजार हिस्से में आई गिरावट के परिणामस्वरूप कीमत कटौती, कम बिक्री तथा घरेलू उद्योग हेतु नियोजित पूँजी पर आय में कमी के रूप में हुई क्षति से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। सम्बद्ध देश से पाटित आयातों के कारण आवेदकों को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 है। तथापि क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल, 2004-मार्च 2005, अप्रैल 2005-मार्च 2006, अप्रैल 2006-मार्च 2007 तथा जांच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

12. सम्बद्ध देश के निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उक्त उत्पाद से सम्बन्धित सम्झे जाने वाले आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जांच में भागीदारी करने के इच्छुक पक्ष निम्नलिखित को लिख सकते हैं :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी,

पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग

कमरा नं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली

समय सीमा

13. वर्तमान जांच से सम्बन्धित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जानी चाहिए जो निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत

14. नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है तो उसके कारण दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्ष अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

16. यदि कोई हितबद्ध पक्ष सूचना जुटाने से मना करता है, अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2008

Subject : Initiation of Anti-Dumping investigations concerning imports of Flax Fabrics originating in or exported from China PR & Hong Kong.

No. 14/8/2008-DGAD.—M/s. Jaya Shree Textiles has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning alleged dumping of Flax Fabrics (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Hong Kong (hereinafter referred to as subject countries).

And, whereas, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject countries, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry

2. Application has been filed by M/s. Jaya Shree Textiles (a unit of Aditya Birla Nuov Ltd.) on behalf of the domestic industry and supported by seven other manufacturers. As per the evidence available applicants have the standing to file the case for anti-dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2 (b) and Rule 5(3)(a) of Anti-Dumping Rules.

Product under consideration

3. The Product Under Consideration is woven fabric having more than 30% flax content. Flax and linen are synonyms and the word "flax" is also known as "Linen" and can be used to produce yarn and fabric made from flax fibres. It is also often used as in generic term to describe a class of woven bed, bath, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels, sheets, etc. In the past, the word also referred to light weight undergarments such as, shirts, chemises, waist shirts, lingerie and detachable shirt collars and cuffs.

4. The product under consideration is classified under Customs Tariff Chapter 53 at sub-heading 53.09. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Like Articles

5. The Petitioner has claimed that there is no significant difference between the products manufactured by them and the subject goods imported from the subject countries: The Flax Fabric produced by the Indian industry and imported in India from China and Hong Kong are comparable in terms of characteristics, such as, physical and chemical characteristics, manufacturing process and

technology, functions and uses, product specification, pricing, distribution and marketing and tariff classification of goods. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are to be treated as Like Articles of the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

Countries Involved

6. The countries involved in the present investigation are China PR and Hong Kong.

Normal Value

7. The applicant have proposed that China being a Non Market Economy the normal value is to be determined in terms of Para 7 of Annex-I of Anti-Dumping Rules. The applicants have stated that they have not been able to procure the prices of the Market Economy Third Country, from such third country to others. Accordingly, the applicants have proposed that Normal Value in respect of China may be determined on the basis of (a) prices in India and (b) cost of production in India, duly adjusted including selling, general and administrative expenses and profit. Petitioner has determined normal value in case of Hong Kong on the basis of constructed normal value.

Export Price

8. The prices available are CIF export prices. The net export price has also been estimated by the applicant based on the CIF price and adopting various elements of adjustments towards ocean freight, commission, etc. to arrive at net export price at exfactory level.

Dumping Margin

9. There are sufficient evidences that the normal value of the subject goods in subject country are significantly higher than their net export price prima facie indicating that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.

Injury and Causal Link

10. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of fall in their market share because of increased volume of dumped imports, price undercutting, lost sales and decline in return on capital employed for the domestic industries. There is sufficient prima facie evidence of the material injury being suffered by the applicants caused by dumped imports from subject country.

Period of Investigation

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 2007 to 31st March, 2008. The injury investigation period will however cover the periods April 2004—March 2005, April 2005—March 2006, April 2006—March 2007 and the Period of Investigation (POI).

Submission of Information

12. The exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping and Allied
Duties,
Ministry of Commerce and Industry,
Department of Commerce,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi.**

Time Limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on

the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

Submission of Information on Non-confidential basis

14. In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

Inspection of Public File

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

16. In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority